

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 28 अगस्त, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरपालिका परिषद, मसूरी को 'रैन बसेरा नव निर्माण कार्य' हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, मसूरी के पत्रांक-9740/अध्यक्ष, दिनांक 20.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, मसूरी के क्षेत्रान्तर्गत किंग्रेग स्थित रैन बसेरा के नवनिर्माण कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, मसूरी को प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) की संस्तुतिनुसार कुल ₹50.45 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल ₹50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I. उक्त धनराशि ₹50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, मसूरी को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- II. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि नगर निकाय द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
- III. स्वीकृत लागत के सापेक्ष ₹46.04 लाख निर्माण कार्यों पर एवं ₹4.41 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार क्रय की जाने वाली सामग्री पर व्यय किया जायेगा।
- IV. स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- V. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- VII. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- VIII. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- IX. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- X. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

9/11



- I. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- II. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- III. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले **Construction Agreement** में एक वर्ष का **Defect Liability Period** तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- IV. धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-13-रैन बसेरों का निर्माण-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 190/XXVII(2)/2015, दिनांक 14.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-S.1508/30.8/.... के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्बाल)  
सचिव।

सं0-349 (1)/IV(2)-शा0वि0-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मीरोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मसूरी।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)  
संयुक्त सचिव।